नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 296
दि. 27.02.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा


## जापान में सीएम योगी ने लिया 600 किमी/घंटा की 'मैग्लेव' का अनुभव, पटरियों पर नहीं बल्कि हवा में तैरती है ये खास ट्रेन

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निवेश की स ंभावना का विस्तार देने जापान दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मैग्लेव ट्रेन में यात्रा की। टोक्यो में हाई-स्पीड मैग्लेव ट्रेन की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रेन की 600 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार का रोमांचक अनुभव लिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जापान दौरे के दौरान टोक्यो में हाई-स्पीड मैग्लेव (Maglev) ट्रेन में सफर किया, जो चुंबकीय शक्ति से हवा में तैरते हुए 600 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार से चलती है। उन्होंने ट्रेन की 100 किलोमीटर की यह परीक्षण यात्रा की, जिसका उद्देश्य यूपी में आधुनिक परिवहन बुनियादी ढांचे

को विकसित करने के लिए नई गति 600-700 किमी/घंटा है, तकनीक को समझना था।

मैग्लेव ट्रेन पारंपरिक पटरियों पर नहीं, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र के सहारे हवा में तैरते हुए चलती है। इस ट्रेन की परिचालन जिससे यात्रा का समय बहुत कम हो जाता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो-नागोया कॉरिडोर के निरीक्षण के दौरान यह सफर किया, जो 2027 तक चालू होने की योजना है। सीएम योगी की यह यात्रा उत्तर प्रदेश में परिवहन के आधुनिक मोर्चों पर चल रही विकास योजनाओं के लिए एक नई दिशा के रूप में देखी जा रही है।

## प्रधानमंत्री 27 फरवरी को 'विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त' विषय पर बजट के बाद आयोजित होने वाले वेबिनार को संबोधित करेंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 फरवरी को प्रातः लगभग 11:30 बजे 'विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त' विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वेबिनार में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने, अवसंरचना विकास, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, वित्तीय क्षेत्र की संरचना को सुदृढ़ करने, पूंजी बाजारों को मजबूत बनाने तथा कर सुधारों के माध्यम से नागरिकों के जीवनयापन को अधिक सरल और सुगम बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

यह वेबिनार केंद्रीय बजट 2026-27 से उभरने वाले प्रमुख विषयों पर आयोजित किये जा रहे बजट पश्चात वेबिनारों की श्रृंखला में पहला है। इन वेबिनारों का उद्देश्य पिछले अनुभवों से सीख लेना और प्रतिभागियों से संरचित प्रतिक्रिया प्राप्त करना है ताकि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट घोषणाओं के परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन को सुदृढ़ और सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें विभिन्न हितधारकों के व्यावहारिक अनुभव और अंतर्दृष्टि का लाभ उठाया जा सके। इनमें उद्योग, वित्तीय संस्थानों, बाजार प्रतिभागियों, सरकार, उद्योग नियामकों और शिक्षा जगत के हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा ताकि प्रमुख बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन मार्गों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

## प्रधानमंत्री मोदी ने 'याद वाशेम' में होलोकॉस्ट पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति हर्जोग संग लगाया 'एक पेड़ मां के नाम'

यरूशलम, 26 फरवरी (आईएएनएस)। इजरायल दौरे के दूसरे दिन, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'याद वाशेम' पहुंचे। नाजी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद प्रेसिडेंशियल गार्डन में राष्ट्रपति हर्जोग के साथ 'एक पेड़ मां के नाम' लगाया।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पोस्ट पर इसे नरसंहार के पीड़ितों को दिया गया सम्मान बताया।

उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस

सेंटर, याद वाशेम का दौरा किया। यह पीएम का याद वाशेम का दूसरा दौरा था। पीएम ने होलोकॉस्ट पीड़ितों को फूल चढ़ाए और श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने दिल को छू लेने वाले बुक ऑफ नेम्स हॉल का भी दौरा किया, जो होलोकॉस्ट के दौरान मारे गए लाखों लोगों की याद को सहेजे हुए है।"

पोस्ट के अनुसार, यह मेमोरियल अतीत की क्रूरता और अन्याय के खिलाफ खड़े होने और एक बेहतर दुनिया बनाने के हमारे मिलकर किए गए इरादे की याद दिलाता है।

प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव राष्ट्रपति हर्जोग से मुलाकात थी।

## भारत और इजरायल जल्द करेंगे फ्री ट्रेड डील, आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं, बोले पीएम मोदी

(जीएनएस)।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 25 फरवरी को दो दिन के राजकीय दौरे पर इजरायल पहुंचे हैं। वे इजरायली समय के अनुसार दोपहर 12.45 बजे बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, जहां उनका बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने स्वागत किया। पीएम मोदी ने दौरे के पहले दिन इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत और इजरायल के संबंधों

पर बात की। दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी ने साझा बयान जारी किया है।

यह प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा इजरायल दौरा है। इससे पहले वह 2017 में भी इजरायल गए थे। नरेंद्र मोदी भारत के इकलौते मंत्री हैं, जिन्होंने इजरायल का दौरा किया है। नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत-इजरायल के बीच हुई रणनीतिक साझेदारी में हुई तरक्की की समीक्षा की है। दोनों नेताओं की विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत पीपुल-टू-पीपुल सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई है।

## उप-राष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने कश्मीर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में महिलाओं का प्रदर्शन सराहनीयः उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति ने स्नातकों से

अनुकूलन और नवाचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर तत्व है

कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का आ'नः 'यह हम सबका कश्मीर है'

दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना लोकतंत्र का मूल आधार हैः उपराष्ट्रपति

## चुंगथांग-लाचेन एक्सिस और ताराम चू ब्रिज का उद्घाटन

(जीएनएस)।

रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने उत्तरी सिक्किम में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा पुनर्निर्मित चुंगथांग-लाचेन मार्ग और 400 फीट लंबे बेली सस्पेंशन ताराम चू पुल का उद्घाटन किया। यह मई-जून 2025 में विनाशकारी बादल विस्फोट, जून 2024 में चक्रवात रेमल और अक्टूबर 2023 में हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ के बाद सीमा सुरक्षा संगठन द्वारा किए जा रहे आपदा राहत प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सीमा सुरक्षा संगठन ने संचार व्यवस्था को बहाल करने के लिए, स्वास्तिक परियोजना के तहत 96 भूस्खलनों को साफ किया, चार प्रमुख पुलों का निर्माण किया और दो अन्य पुलों की मरम्मत की। सीमा सुरक्षा संगठन की इंजीनियरिंग टीम ने 8 किलोमीटर की नई भू-सफाई पूरी की

और अस्थिर ढलानों और धंसने वाले क्षेत्रों से निकलने के लिए विभिन्न वैकल्पिक मार्ग बनाए। ये प्रयास अक्टूबर 2025 में 7.5 किलोमीटर लंबे नागा-टूंग मार्ग के खुलने के बाद किए गए हैं, जिससे क्षेत्र में संपर्क और मजबूत हुआ है। 28 किलोमीटर लंबी चुंगथांग-लाचेन सड़क और ताराम चू पुल के पूरा होने से स्थानीय निवासियों, सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि ये परिसंपत्तियां उत्तरी सिक्किम के बुनियादी ढांचे के विकास और स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने क्षेत्र में लगातार किए जा रहे कार्यों के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की। इन महत्वपूर्ण सड़क संपर्क सुविधाओं का उद्घाटन सिक्किम के मुख्यमंत्री द्वारा उल्लिखित 'आत्मनिर्भर सिक्किम-विकसित भारत विजन' के अनुरूप है।

## कायाचिकित्सा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी) ने श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल में 23 से 24 फरवरी 2026 तक कायचिकित्सा पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

उद्घाटन समारोह में डॉ. वंदना सिरोहा, निदेशक, आरएवी; प्रो. प्रसन्ना नरसिम्हा राव, निदेशक, एसडीएम आयुर्वेद संस्थान, एसडीएम एजुकेशनल सोसाइटी, उजिरे; डॉ. शैलजा उप्पिनाकुदुरू, प्रिंसिपल, एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड हॉस्पिटल, हसन और डॉ. बीजी गोपीनाथ, पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, कायाचिकित्सा विभाग, सरकारी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मैसूरु और पूर्व डीन, श्री श्री आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु सहित कई

विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

शैक्षणिक सत्रों को इस क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया, जिनमें एसडीएम आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल, हसन के कायाचिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉ. तोताद मुत्तप्पा; जेएसएस आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मैसूरु की कायाचिकित्सा की प्रोफेसर डॉ. वीणा जी. राव; और मगनभाई अदेनवाला महागुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति वैद्य एस.एन. गुप्ता शामिल थे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद चिकित्सकों के कायाचिकित्सा क्षेत्र में नैदानिक ज्ञान को सुदृढ़ करना और उनकी शैक्षणिक एवं व्यावहारिक दक्षताओं को बढ़ाना था। प्रतिभागियों ने समकालीन नैदानिक अनुप्रयोगों और आयुर्वेदिक आंतरिक चिकित्सा में हुई प्रगति पर केंद्रित संवादमूलक चचाओं और विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले सत्रों में भाग लिया।

## 'शिल्प समागम केवल मेला नहीं, आत्मनिर्भरता और सम्मान का सेतु है' - डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 'शिल्प समागम-2026' का किया उद्घाटन

'यह केवल उत्पादों की प्रदर्शनी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और सामाजिक सशक्तिकरण का उत्सव है।' इन शब्दों के साथ केंद्रीय सामाजिक

न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज अहमदाबाद के 'वल्लभ सदन', साबरमती रिवरफ्रंट में आयोजित 'शिल्प समागम मेला-2026' का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी उपस्थितजनों को आगामी होली पर्व की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह मेला देश के लक्षित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में मंत्रालय की सतत प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

## सीडीएस ने दो दिवसीय सीबीआरएन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा 26 और 27 फरवरी, 2026 को मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (सीबीआरएन) कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। 'नीति से अभ्यास तकः सीबीआरएन लचीले भारत का निर्माण' विषय पर आधारित इस सम्मेलन का उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया। यह आयोजन सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ आदि के विभिन्न विशेषज्ञों और नीति निमार्ताओं को एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य सीबीआरएन खतरों के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करना है।

अपने संबोधन में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सीबीआरएन रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में डीआरडीओ द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "सीबीआरएन को एक खतरे के बजाय एक वातावरण के रूप में अधिक देखे जाने की आवश्यकता है,

और हमें दूषित वातावरण में रहने और काम करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए।" उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम, हल्के वजन वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और गैजेट्स, अच्छी तरह से शोध किए गए एसओपी और सैन्य एवं नागरिक प्रतिष्ठानों के साथ तालमेल बिठाकर समन्वित संचालन करने के लिए स्वदेशी और अत्याधुनिक सीबीआरएन रक्षा उपकरणों के साथ तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

रक्षा आर एंड डी विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने अपनी विशिष्ट प्रयोगशालाओं और केंद्रों के माध्यम से सीबीआरएन सक्षम भारत बनाने की डीआरडीओ की प्रतिबद्धता व्यक्त की, जो विशेष रूप से सीबीआरएन खतरों से रक्षा के लिए उन्नत तकनीक विकसित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सम्मेलन के प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे इसे आपसी सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करें

## 'साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0' के विजेताओं का सम्मान

(जीएनएस)।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सचिव श्री एस. कृष्णन ने आज मंत्रालय की एक प्रमुख पहल 'साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0' (जीएसजीसी 2.0) के विजेताओं को सम्मानित किया। यह पहल भारत में डेटा संरक्षण पर केंद्रित एक गैर-लाभकारी उद्योग निकाय डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) के सहयोग से कार्यान्वित की गई है। इस पहल का उद्देश्य देश की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और एक सुरक्षित एवं सुदृढ़ डिजिटल तंत्र को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता का निर्माण करना है।

साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 में कुल 6.85 करोड़ रुपये का पुरस्कार पूल था जिससे यह देश में सरकार द्वारा समर्थित सबसे महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा नवाचार चुनौतियों में से एक बन गया। ग्रैंड चैलेंज 2.0 के विजेताओं को ट्रॉफी और एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया, जबकि प्रथम और द्वितीय उपविजेताओं को क्रमशः 50 लाख रुपये और 25 लाख रुपये प्राप्त हुए।

विजेताओं की सूची और उनके द्वारा हल की गई समस्याएं इस प्रकार हैं:

स्टार्ट-अप : समस्या विवरण का समाधानविजेता, कैम्ब्रियन स्किल्सडा टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज एलएलपी (सीएसटीसीएस), अगली पीढ़ी के बायोमेट्रिक सिस्टम को सुरक्षित करना, प्रथम उपविजेता, क्रिप्सिस, क्लोन और नकली ऐप्स से बचाव

द्वितीय उपविजेता

जिरिजडॉटएआई, एपीआई सुरक्षा

जनवरी 2025 में माईगव प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई साइबर

सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज, छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित कर हमारे देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इन क्षेत्रों में एपीआई सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, पहनने योग्य उपकरणों की सुरक्षा और गोपनीयता, क्लोन और नकली ऐप का निवारण, खतरे का पता लगाने और घटना प्रतिक्रिया के लिए एआई, और अगली पीढ़ी के बायोमेट्रिक सिस्टम को सुरक्षित करना शामिल है। इस पहल की एक अनूठी विशेषता यह है कि विकसित समाधानों के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संबंधित स्टार्ट-अप के पास हैं।

यह चैलेंज चार व्यवस्थित चरणों में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक स्तर पर क्रमिक मूल्यांकन और वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आइडिया स्टेज में, प्रत्येक समस्या विवरण के तहत छह स्टार्ट-अप्स का चयन किया गया, जिससे कुल 36 स्टार्ट-अप्स हो गए और प्रत्येक को अपने समाधानों को और विकसित और परिष्कृत करने के लिए पांच लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया।

न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादन चरण के दौरान इन स्टार्ट-अप्स को कार्यात्मक प्रोटोटाइप बनाने के लिए व्यवस्थित तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसके बाद 18 स्टार्ट-अप्स (प्रत्येक समस्या विवरण के तहत तीन) अंतिम उत पाद चरण में पहुंचे और प्रत्येक को 10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। इस चरण में समाधानों का परीक्षण और सत्यापन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पांच स्टार्ट-अप्स का चयन हुआ और प्रत्येक को 25 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। अंतिम गो-टू-मार्केट स्टेज में स्टार्ट-अप्स का मूल्यांकन व्यावसायिक तत्परता मापनीयता और बाजार क्षमता के आधार पर किया गया और तीन स्टार्ट-अप्स को शीर्ष विजेता घोषित किया गया। पूरे चैलेंज के दौरान भाग लेने वाले स्टार्ट-अप्स को उत्पाद की परिपक्वता, तैनाती क्षमता और बाजार तत्परता को मजबूत करने के लिए निरंतर तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

एमईआईटीवाई के सचिव श्री एस. कृष्णन ने कहा, 'साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज 2.0 देश में मजबूत स्वदेशी साइबर सुरक्षा क्षमता के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साइबर सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां घरेलू क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा में स्वदेशीकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियां वास्तविक और लगातार बदलती रहती हैं, और हमें अपने स्वयं के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विकसित समाधानों के साथ तैयार रहना चाहिए।'

इस चैलेंज के लिए एक कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई है, और इसमें छात्रों के नेतृत्व वाली टीमों, स्टार्ट-अप्स और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों सहित व्यापक भागीदारी देखकर उत्साहजनक है। समस्या विवरण सावधानीपूर्वक तैयार किए गए थे और आज की डेटा-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं, जहां एपीआई जैसे तंत्रों के माध्यम से डेटा साझाकरण में वृद्धि के साथ-साथ मजबूत डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुरक्षा उपायों का होना आवश्यक है। यह पहल दीर्घकालिक घरेलू क्षमता निर्माण को जारी रखने का एक अवसर है और हमें भविष्य में भी इस गति को बनाए रखना होगा। एमईआईटीवाई साइबर सुरक्षा में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और निरंतर सहयोग के माध्यम से संस्थागत और प्रणाली क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

# परिवर्तन चौक पर पुलिस की छात्रों से नोकझोंक:बोले- लखनऊ विश्वविद्यालय आरएसएस का अड्डा बना, डीएम ऑफिस कूच किया

लखनऊ, (जीएनएस)। लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित लाल बारादरी सील किए जाने के विरोध में बापसा, भाकपा माले और आइसा के छात्रों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन पर रोक होने के कारण परिवर्तन चौक से स्वास्थ्य भवन चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए।

डीएम ऑफिस जाने पर अड़े प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान गुप्ता ने स्वास्थ्य भवन चौराहे पर ही पहुंचकर उनका ज्ञापन लिया। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का अड्डा बना दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के बाद लाल बारादरी सील किया गया है।

इसके पहले 25 फरवरी की रात तौकील गाजी ने इस संबंध में एक वीडियासे जारी किया था। उसमें कहा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने लाल बारादरी पर ताला लगा दिया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने विश्वविद्यालय में लगातार 2 दिन तक धरना दिया। विश्वविद्यालय प्रॉक्टर ने बातचीत करके 2 दिनों का समय मांगा था, लेकिन वह बीत गया।

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ताला खोलने को लेकर कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। न ही दोबारा कोई बातचीत की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 25 फरवरी को नोटिस जारी करके परिसर में किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दिया है।

# वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं देना चाहती केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेगी पार्टी - चेतन शर्मा

**अभिनव भारत पार्टी के अधिवेशन में जुटे देश के साधु-संत**

लखनऊ। क्रान्तिकारी स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर आज यहां इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुये अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा करते हुये कहा है कि केन्द्र सरकार वीर सावरकर को भारत-रत्न देने के लिये गंभीर नहीं है। अधिवेशन में पार्टी के सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि वीर सावरकर ने अपने युवावस्था में ही अभिनव भारत संगठन की स्थापना कर पराधीन भारत में क्रान्ति की ज्वाला प्रज्जवलित की थी, उन्होंने केवल स्वतंत्रता का स्वप्न नहीं देखा बल्कि उसके लिये कालकोठरी में अमानवीय यातनायें सही। अंडमान की सेल्युलर जेल की दीवारें आज भी उस तप, त्याग और तेज की साक्षी है, ऐसे व्यक्तित्व को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वीर सावरकर को भारत रत्न दिये जाने को लेकर कह चुके है कि सावरकर के योगदान को देखते हुये यदि उन्हें भारत-रत्न मिलता है तो इससे भारत-रत्न का सम्मान होगा। श्री शर्मा ने बताया कि अभिनव पार्टी ने पिछले वर्ष वीर सावरकर को भारत-रत्न दिलाने की मांग को लेकर देशभर में सावरकर सम्मान यात्रा निकालकर देश की राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित आठ सौ ज्ञापन देश के विभिन्न हिस्सों से दिये गये, लेकिन इसके बावजूद केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई विचार नहीं कर रही है, इसके लिये पार्टी निरन्तर संघर्ष करती रहेगी।

श्री शर्मा ने अधिवेशन में पारित प्रस्तावों को लेकर कहा कि देश में गाय की सुरक्षा के लिये माता का दर्जा देने के साथ-साथ उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाये, तभी जाकर देश में गाय माता को बचाया जा सकता है। गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा केवल भावनात्मक निर्णय नहीं होगा बल्कि यह एक ठोस कानूनी संरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चेतन शर्मा ने कहा कि अभिनव भारत पार्टी राज्य के चुनावी रणभूमि में उतरने के लिये पूरी तरह तैयार है, और लगभग तीन सौ सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। चुनावी रणनीति को लेकर अभिनव भारत पार्टी जल्द ही अन्तिम रूप देकर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर जायेगी।

इससे पहले इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में अधिवेशन का शुभारम्भ भारत माता की स्तुति और वन्देभारत गीत के साथ दीप प्रज्जवलित कर हुआ। इस मौके पर प्रमुख रूप से मालेगांव मामले में बरी हुये मेजर रमेश उपाध्याय, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री कम्प्यूटर बाबा, पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री ममता झा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. नीलेन्द्र गौतम, श्रीमती चित्रा दलाल, स्वरूपानंद महाराज के शिष्य त्रिभुवन दास, कार्तिक गिरी, सर्वेश मिश्रा, महामण्डलेश्वर अमरेशानन्द गिरी सहित देशभर से आये पार्टी के कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि मौजूद थे।

# बीमार बच्ची के इलाज के लिए ससुराल पहुंची महिला से मारपीट का आरोप

खखरेरू / फतेहपुर थाना क्षेत्र के शाहनगर गांव की निवासी फरजाना बेगम ने अपने ससुरालीजनों पर मारपीट और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। महिला का कहना है कि वह अपनी बीमार एक वर्षीय बच्ची के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने ससुराल गई थी, जहां उसके साथ मारपीट की गई।

पुलिस को दी गई तहरीर में फरजाना बेगम ने बताया कि उसका पति मेहताब खाड़ी देश में रहकर नौकरी करता है। आरोप है कि कुछ समय पूर्व ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे उसके तीन बच्चों सहित घर से निकाल दिया था। इसके बाद से वह अपने मायके में रहकर मेहनत-मजदूरी कर बच्चों का पालन-पोषण कर रही है।

महिला के अनुसार हाल ही में उसकी एक वर्ष की मासूम बच्ची गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इलाज कराया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उपचार में दिक्कत आने लगी। मजबूर होकर वह 24 फरवरी को अपने ससुराल मदद मांगने पहुंची।

आरोप है कि वहां देवर इमरान उर्फ नन्नू, जेठ अल्ताफ तथा ननद साजिया ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से मारपीट की। महिला का कहना है कि सहायता करने के बजाय उसे अपमानित किया गया और धमकी दी गई कि उसका पति विदेश में बैठा है, वह उसे छोड़ देगा।

घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

इस संबंध में थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर ससुरालीजनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

# डॉ. आनंद प्रकाश मिश्र, वो डॉक्टर, जिसने मंच को बनाया समाज सुधार का नश्तर

आमतौर पर एक डॉक्टर का काम अस्पताल की चारदीवारी तक सीमित रहता है, लेकिन शाहजहाँपुर के डॉ. आनंद प्रकाश मिश्र ने इस धारणा को बदल दिया। 1957 में हरदोई के ग्राम घसा में जन्मे डॉ. मिश्र ने महसूस किया कि शरीर के रोगों से कहीं ज्यादा खतरनाक समाज में फैली कुरीतियाँ और अज्ञानता है। बस, यहीं से शुरू हुआ चिकित्सा सेवा से समाज सेवा तक का एक अनूठा सफर।

डॉ. मिश्र ने केवल दवाइयाँ नहीं दीं, बल्कि कलम उठाकर नाटक लिखे और खुद मंच पर उतरकर समाज को आईना दिखाया। उनकी पत्नी नलनी मिश्रा ने भी हर कदम पर उनका साथ दिया और नाटकों में मुख्य भूमिकाएँ निभाकर इस मिशन को नई ताकत दी। उनकी संस्था 'सजन समाज सेवा समिति' ने देश के कोने-कोने में चेतना जगाई।

डॉ. मिश्र के नाटकों ने समाज के हर दुखते नस पर प्रहार किया, नशा मुक्ति पतन स्मैक/गुटखा के खिलाफ और फैसला, बिदा टीबी पर और एक ही भूल पोलियो पर भागीरथी और गंगा मैया भला करें, कन्या भ्रूण हत्या, स्वच्छता, नारी सशक्तिकरण और जनसंख्या विस्फोट।

उनकी कला और जुनून का जादू ऐसा था कि शक्ति कपूर, सुदेश बेरी और अली खान जैसे बॉलीवुड कलाकार भी शाहजहाँपुर खिंचे चले आए। उनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए उन्हें 'जनपद रत्न' जैसे कई सम्मान मिले। चर्चा है कि उनके समर्पण के कारण अब उन्हें सेंसर बोर्ड की सदस्यता और जल संरक्षण के लिए जल पुरुष सम्मान से भी नवाजा जा सकता है।

डॉ. आनंद प्रकाश मिश्र ने यह साबित कर दिया कि हीरो सिर्फ पर्दे पर नहीं होते। जब एक पेशेवर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को सामाजिक मिशन बना लेता है, तो वह केवल व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच का उपचार करता है। उनका पूरा परिवार जिसमें डॉक्टर और विशेषज्ञ शामिल हैं, आज समाज के लिए एक मिसाल है।

# सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल अधेड़ इलाज के दौरान तोड़ा दम

(जीएनएस)।

फतेहपुर। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के नाज भट्ठा स्थित कोल्ड स्टोर के पास बुधवार की रात को शादी समारोह में शामिल होने जा रहे दो बाइकों की आमने-सामने की भिंड़त में तीन लोगों की मौत हो गई थी और दो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसमें एक की गुरुवार को सुबह अस्पताल मौत हो गई।

थाना क्षेत्र के तौरा गांव निवासी नरेश पासवान के पुत्र कंधई की बुधवार को शादी थी। बरात में शामिल होने नरेश के साले मोतीलाल पासवान (40) निवासी मोहम्मदपुर गौंती अपने पुत्र धर्मेंद्र के साथ मोटरसाइकिल से तथा समधी कमलेश कुमार पासवान (60) निवासी भैरवां कला साइकिल से शाम को गांव पहुंचे। दोनों लोग गांव के ही पड़ोसी दुर्गेश पासवान (23) की मोटरसाइकिल में बैठकर शाहपुर के पास रसूलपुर गांव बरात के लिए निकले। वहीं दूसरी ओर हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई पतारा गांव निवासी रामू (33) अपने भतीजे अरविंद (23) के साथ बाइक से खागा कोतवाली के कल्लनपुर गांव निमंत्रण में जा रहे थे। दोनों बाइकों की कोल्ड स्टोर के पास भिड़ंत हो गई। जिससे पांचों लोग घायल हो गए। पुलिस इन्हें हथगाम ले गई। यहां चिकित्सक ने अरविंद, दुर्गेश और कमलेश को मृत घोषित कर दिया था और गंभीर रूप से घायल रामू और मोतीलाल को सदर अस्पताल रेफर कर दिया था। इसमें मोतीलाल पासवान की भी गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक मोतीलाल मजदूरी का कार्य करते थे। परिवार में पत्नी आशा, पुत्र राजेन्द्र कुमार, घनश्याम कुमार, धर्मेंद्र कुमार पुत्री सविता देवी हैं। कमलेश कुमार भी मजदूरी का कार्य करते थे। परिवार में पत्नी मैकी देवी, पुत्र रंजीत कुमार, श्रवण कुमार, सचिन, शिवा, पुत्री गुड़िया, माया, सीमा, सरिता, कमला हैं। मृतक दुर्गेश कमाने के वास्ते बाहर रहता है। परिवार में मां केशपती, भाई सियम्बर, बृजेश और बहन सोना हैं। 1 माह पहले दुर्गेश मुम्बई से कमाकर घर आया था। उसकी करीब 4 माह पहले गड़रियन का पुरवा गांव में सगाई तय हो गई और बयाना हो गया था और शादी की तारीख रखना बांकी था।

# अवैध कब्जे का आरोप, जिलाधिकारी से की गई कार्रवाई की मांग

(जीएनएस)।कौशाम्बी

चायल तहसील क्षेत्र के ग्राम पेरई तिलहापुर मोड़ में स्थित श्री सीताराम स्थानीय संत सेवा समिति एवं ट्रस्ट की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है संगठन के महामंत्री महेश्वरदास ने जिलाधिकारी को लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया है कि ट्रस्ट की जमीन, गाटा संख्या 218 पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त भूमि धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुरक्षित है, जिस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अस्वीकार्य है महामंत्री ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर अवैध कब्जा तत्काल हटवाया जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि तहरीर प्राप्त हुई है और मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी स्थानीय लोगों में भी इस प्रकरण को लेकर चर्चा है और वे प्रशासन से निष्पक्ष व त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं

# लखनऊ के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. पी. सी. गुप्ता को भारतीय डिजाइन पेटेंट प्राप्त

लखनऊ।

लखनऊ स्थित प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश डॉ. पी. सी. गुप्ता को AI based Device for business strategy planning and risk forecasting' शीर्षक से विकसित नवाचार हेतु भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा डिजाइन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। यह पंजीकरण डिजाइन अधिनियम, 2000 एवं डिजाइन नियम, 2001 के अंतर्गत प्रदान किया गया है यह अभिनव डिजाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित उपकरण से संबंधित है, जो व्यवसायिक रणनीति निर्माण एवं जोखिम पूर्वानुमान में सहायक है। यह उपकरण आधुनिक आर्थिक विश्लेषण, डेटा आधारित निर्णय-निर्माण तथा संस्थागत प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस उपलब्धि में डॉ. पी. सी. गुप्ता के साथ अन्य सह-आविष्कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें डॉ. महेन्द्र कुमार नामदेव, डॉ. मुस्ताक आलम, पूजा उपाध्याय, डॉ. किरण सचदेवा, डॉ. श्वेता सिंह, सुमोना घोष, विशाल मिश्रा, अवधेश यादव एवं अपराजिता श्रीवास्तव शामिल हैं। डॉ. पी. सी. गुप्ता, जो कि लखनऊ के एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् एवं अर्थशास्त्री हैं, एवं डॉ. मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ अर्थशास्त्री द्वारा भी अपनी अर्थशास्त्र पर पुस्तकों हेतु सराहना पत्र एवं मार्गदर्शन पा चुके है ने इस उपलब्धि को शिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार के समन्वय का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह डिजाइन भविष्य में उद्योग, शिक्षा एवं नीति-निर्माण के क्षेत्र में रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावी बनाएगा। शैक्षणिक एवं बौद्धिक जगत में इस उपलब्धि को अत्यंत गौरवपूर्ण माना जा रहा है। यह न केवल संस्थान बल्कि लखनऊ शहर एवं प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है।

# मूरतगंज ब्लॉक के पक्सराई गांव में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण में बड़ा घोटाला, मानकों की अनदेखी

कौशाम्बी

मूरतगंज विकास खंड अंतर्गत पक्सराई गांव में बन रहे सरकारी अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं निर्माण में मानक के विपरीत रद्दी किस्म की बालू और घटिया ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान की घोर लापरवाही के चलते सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और निर्माण कार्य में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है जो कानूनन अपराध है पढ़ाई-लिखाई की उम्र में बच्चों को मजदूरी में झोंककर उनका भविष्य खराब किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोग आंख मूंदे बैठे हैं

इतना ही नहीं, अन्त्येष्टि स्थल के ठीक बगल स्थित सरकारी तालाब की खुदाई मानकों से कहीं अधिक कराई गई है।

सूत्र JCB मशीन लगवाकर जरूरत से ज्यादा खुदाई कराई गई और निकाली गई मिट्टी को ग्राम प्रधान द्वारा बेच दिया गया इससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ तालाब के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है

## जिला मजिस्ट्रेट ने 04 मार्च को आबकारी की समस्त दुकानों के बन्द रखने के दिए आदेश

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए होली पर्व के अवसर पर कानून-व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जनपद कौशाम्बी में संचालित समस्त देशी शराब/कम्पोजिट मदिरा/भाँग/एफ.एल.-16/17, एफल.एल.-2, 2बी. एवं सी.एल.-2 आदि मादक पदार्थों के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानों को होली (रंग खेले जाने वाले सम्पूर्ण) दिनांक 04 मार्च,2026 को बन्द रखने का आदेश दिया है। इस प्रकार अनुज्ञापनों को बन्द रखने के लिये सम्बन्धित अनुज्ञापियों को नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया है कि इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

**जिला मजिस्ट्रेट ने 04 मार्च को आबकारी की समस्त दुकानों के बन्द रखने के दिए आदेश**

कौशाम्बी। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए होली पर्व के अवसर पर कानून-व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जनपद कौशाम्बी में संचालित समस्त देशी शराब/कम्पोजिट मदिरा/भाँग/एफ.एल.-16/17, एफल.एल.-2, 2बी. एवं सी.एल.-2 आदि मादक पदार्थों के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानों को होली (रंग खेले जाने वाले सम्पूर्ण) दिनांक 04 मार्च,2026 को बन्द रखने का आदेश दिया है। इस प्रकार अनुज्ञापनों को बन्द रखने के लिये सम्बन्धित अनुज्ञापियों को नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया है कि इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

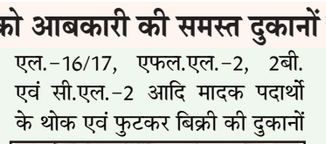

# ग्लोबल एग्रोटेक 2026 के पहले दिन बी.एल. एग्रो ने प्रस्तुत की अपनी विविध क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला

**लखनऊ में 3 दिवसीय प्रदर्शनी-संगोष्ठी का उद्घाटन कृषि मंत्री ने किया**

**उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री, श्री ब्रजेश पाठक ने बीएल एग्रो के स्टॉल का उद्घाटन किया।**

लखनऊ, 26 फरवरीः भारत के अग्रणी एग्रो-उत्पाद ब्रांड बी.एल. एग्रो ने गुरुवार को लखनऊ स्थित करफक्क -भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (करफक्क) में शुरू हुए 'ग्लोबल एग्रोटेक 2026' प्रदर्शनी एवं सम्मेलन के पहले दिन अपनी विविध क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया।तीन दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन श्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर कृषि क्षेत्र के रूपांतरण के लिए एकीकृत मंच पर वरिष्ठ नीति-निमार्ताओं, अंतरराष्ट्रीय राजनयिकों, शोध संस्थानों, उद्योग जगत के नेताओं और प्रगतिशील किसानों की सहभागिता रही। उद्घाटन समारोह में दिनेश प्रताप सिंह, माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उद्यान, कृषि विपणन एवं निर्यात तथा रविंदर, आईएएस, प्रमुख सचिव, कृषि भी उपस्थित रहे।

श्री पाठक ने बीएल एग्रो ग्रुप के पवेलियन का उद्घाटन किया और उन्हें कृषि-खाद्य प्रसंस्करण, एकीकृत वैल्यू चेन, डेयरी विकास, वैज्ञानिक जेनेटिक्स एवं जीनोमिक्स, एग्रीटेक प्लेटफॉर्म तथा क्लाइमेट-टेक आधारित जोखिम बुद्धिमत्ता ढाँचों सहित समूह के सक्रिय योगदानों के बारे में जानकारी दी गई। बीएल एग्रो की सहायक कंपनियों— लीड्स कनेक्ट, लीड्स जेनेटिक्स और लीड्स इंश्योरेंस ब्रोकर्स —ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जो कृषि की एकीकृत वैल्यू चेन में समूह की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है।

कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर श्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'उत्तर प्रदेश कृषि उन्नति और खाद्य प्रसंस्करण उत्कृष्टता का एक तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। बीएल एग्रो जैसी कंपनियों की इस तरह के मंचों पर भागीदारी उत्तर प्रदेश की एग्री-इनोवेशन, वैल्यू एडिशन और किसान सशक्तिकरण में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। ऐसे प्रयास तकनीक, उद्यम और ग्रामीण विकास के बीच सेतु को मजबूत करते हैं। मैं राज्य की कृषि प्रगति में निरंतर योगदान के लिए बीएल एग्रो को शुभकामनाएं देता हूँ।'

उद्घाटन अवसर पर माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उद्यानिकी, कृषि विपणन एवं निर्यात श्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, 'यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम भारतीय कृषि के अगले विकास चरण पर चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय कृषि में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। सतत कृषि के लिए सफल पीपीपी मॉडल ही आगे का मार्ग है। ऐसे आयोजन सभी हितधारकों को एक साथ लाकर स्थायी भविष्य की दिशा में कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं।'

कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए घनश्याम खंडेलवाल, चेयरमैन, बी.एल. एग्रो एवं कऋऋ वढरअउ ने कहा 'तीन दिवसीय ग्लोबल एग्रोटेक देश के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह क्षेत्र भारतीय ऋछढ में सबसे बड़े योगदानकताओं में से एक है और आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है। यह उद्योग वर्तमान में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इसलिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाकर भविष्य के लिए एक बड़ा कदम उठाने की जिम्मेदारी हम पर है। आज हमने उत्तर प्रदेश की कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने, डेयरी के आधुनिकीकरण में तेजी लाने, एग्री-फाइनेंस की पहुंच बढ़ाने और प्रौद्योगिकी-सक्षम कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। ग्लोबल एग्रोटेक 2026 उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करने के लिए एक एकीकृत और बुद्धिमत्ता-आधारित कृषि व्यवस्था के निर्माण की दिशा में हमारा प्रयास है—जहां नीति दृष्टि, वैज्ञानिक प्रगति और निजी क्षेत्र का क्रियान्वयन एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।'

उद्घाटन दिवस पर 'उत्तर प्रदेश कृषि विकास बैठक' का आयोजन होटल रेडिसन, लखनऊ में किया गया, जिसकी अध्यक्षता बी.एल. एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं कऋऋ वढरअउ चेयरमैन श्री घनश्याम खंडेलवाल ने की। इस बैठक में श्री मुकेश कुमार मेश्राम (आईएएस), अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन, तथा श्री रविंदर( आईएएस) प्रमुख सचिव, कृषि भी उपस्थित रहे। साथ कोट डी'आइवोर, क्यूबा, स्पेन और ब्राजील के राजनयिक प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की।डेवलपमेंट मीट में पशुधन और डेयरी क्षेत्र के रूपांतरण पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर ब्राजील की अग्रणी डेयरी जेनेटिक्स एवं फार्म मैनेजमेंट कंपनी 'फजेंडा फ्लोरेस्टा' के संस्थापक रोजेरियो बारोस एवं रोबर्टा बर्टिन बारोस भी मौजूद थे। उन्होंने दूध उत्पादन बढ़ाने और स्वदेशी नस्लों को सुदृढ़ करने में वैज्ञानिक प्रजनन, जीनोमिक्स तथा प्रजनन तकनीकों की भूमिका को रेखांकित किया।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

# सम्पादकीय

## ट्रंप की धमकी रमजान की तैयारियों के आगे फीकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हमले की लगातार धमकियों के बीच ईरान में रमजान को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार ईरान के भीतर सार्वजनिक जीवन नियमित रूप से चल रहा है। उधर ईरान से सटे इलाके में अमेरिकी सेना की लगातार बढ़ती तैनाती अब सिर्फ संकेत देने तक सीमित नहीं लगती बल्कि ये वास्तविक जंग के स्पष्ट संकेत हैं। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहिम लिंकन और यूएसएस फोर्ड के ईरानी जल क्षेत्र के पास पहुंचने से स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा सैकड़ों अमेरिकी फाइटर जेट व अन्य साजोसामान भी इस इलाके में पिछले वुछ दिनों में लाए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका-इजराइल यहां कई स्तरों पर सैन्य कार्रवाई के लिए विकल्प तैयार कर रहे हैं। ईरान में यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। जंग की आहट के बावजूद ईरान में सब सामान्य दिख रहा है। मस्जिदों में विशेष नमाज, बड़े इफ्तार आयोजन और सदका-फितर प्रमुखता से हो रहे है। इस्लामिक रिपब्लिकन न्यूज एजेंसी ने रमजान के अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का संदेश प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने इस महीनों को आत्मचिंतन और एकजुटता का समय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की शक्तियां हमें अपना सिर झुकाने के लिए साजिश कर रही हैं... लेकिन ये हमारे लिए जो भी समस्याएं पैदा करें, हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो इससे पश्चिम एशिया में एक क्षेत्रीय (रीजनल) युद्ध छिड़ सकता है, तनाव और अधिक बढ़ सकता है। खामनेई ने कहा कि ईरान उकसाने की नीति नहीं अपनाता लेकिन उन्होंने साफ किया कि ईरानी राष्ट्र पर अगर कोई हमला या उत्पीड़न किया गया तो ईरान ऐसा कड़ा जवाब देगा जिसका अमेरिका-इजराइल को अंदाजा नहीं। हम पर कोई भी स्ट्राइक हो चाहे वह लिमिटेड स्ट्राइक ही क्यों न हो पर उसका पूरी ताकत से जवाब देंगे। मध्यपूर्व के तमाम अमेरिकी सैन्य बेसों सहित उनके युद्धपोत भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार अपनी शर्ते बदल रहे हैं। पहले उन्होंने तीन शर्ते रखी थीं: ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करे, अपनी मिसाइलों की प्रोडक्शन और क्षमता कम करे। ईरान से अमेरिका की इस सिलसिले में दो बार जेनेवा में वार्ता विफल हो चुकी है। अब तीसरे और अंतिम राउंड की बात हो रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन से बेहतर वुछ हो ही नहीं सकता। अमेरिका इन तरीकों से ईरान को घेरने की युद्ध नीति पर काम कर रहा है। जंगी जहाजों की तैनाती, अरब सागर में तैनात अमेरिका के विशाल विमान वाहक पोतों को घेरने की है। पहले बड़ी संख्या में टैंक से जहाजों के सुरक्षा सिस्टम को उलझाएंगे, ताकि वे मिसाइल को रोकने में कामयाब रहें। दूसरी: खाड़ी देशों के मौजूद अमेरिका के 19 ठिकानों पर करीब 50, 000 सैनिक किसी भी समय हमले में भाग ले सकते हैं। हालांकि यही सैनिक ईरान के निशाने पर होंगे। तीसरा: तेल सप्लाई रोकना। अमेरिका इस प्रयास में है कि ईरान किसी भी देश को अपने यहां से तेल सप्लाई न कर सके ताकि उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़े। उसने भारत पर भी दबाव डाला है कि भारत ईरान से तेल लेना बंद करे। इस बीच इजराइल से एक अपुष्ट खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि इजराइल ने अब चेतावनी दी है कि अगर उसके अस्तित्व पर खतरा हुआ तो वह ऐसे हथियार चलाएगा जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं। इशारा साफ है कि परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकता है। वुल मिलाकर बड़ी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। उम्मीद की जाती है कि जंग टले क्योंकि अगर यह होती है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ सकता है।

# पुडुचेरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के लिए सीबीडीसी आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा का पायलट परियोजना शुरू

**केंद्र सरकार ने पुडुचेरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के लिए सीबीडीसी आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा का पायलट परियोजना शुरू किया**

**पुडुचेरी में लाभार्थियों के पारंपरिक बैंक खातों के बजाय सीबीडीसी वॉलेट में खाद्य सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण किया जाएगा, यहाँ वर्तमान में डीबीटी मॉडल के माध्यम से पीडीएस लागू किया जा रहा है**

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सीबीडीसी का एकीकरण पारदर्शी और सशक्त खाद्य वितरण प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम है: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी**

**'हर दाना, हर रुपया, हर हक' - केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सीबीडीसी आधारित डिजिटल खाद्य कूपन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया**

**'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' सभी को प्रयास करना चाहिए: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी**

(जीएनएस)।

केंद्र सरकार ने पुडुचेरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) हेतु केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज पुडुचेरी में उपराज्यपाल श्री के. कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री श्री एन. रंगासामी की उपस्थिति में ने इसका उद्घाटन किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की शुरूआत भारत की खाद्य सुरक्षा संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) का एकीकरण पारदर्शिता, दक्षता और लाभार्थियों के सशक्तिकरण को बढ़ाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उनके हक अधिक स्पष्टता और जवाबदेही के साथ प्राप्त हों। "हर दाना, हर रुपया, हर हक" के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि यह सुधार हकों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा, सुरक्षित और वास्तविक समय के लेनदेन को सक्षम करेगा और कल्याणकारी वितरण तंत्र के भीतर डिजिटल इंडिया पहल को और अधिक मजबूत करेगा।

श्री जोशी ने बताया कि सीबीडीसी प्रणाली के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए डिजिटल कूपन लाभार्थियों के खातों में प्रोग्रामेबल डिजिटल करेंसी (ई₹) के रूप में सीधे जमा किए जाएंगे। लाभार्थी सीबीडीसी कूपन या वाउचर कोड का उपयोग करके उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) या व्यापारी आउटलेट्स से अपनी निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रणाली सुरक्षित, ट्रैक करने योग्य और वास्तविक समय में लेनदेन सुनिश्चित करते हुए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ई-पीओएस परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करेगी। उन्होंने बताया कि पीएमजीकेएवाई विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। यह न केवल गेहूं और चावल बल्कि लाभार्थियों को बाजरा भी प्रदान कर रहा है, जिससे पोषण सुरक्षा मजबूत हो रही है।

श्री जोशी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने यह दर्ज किया है कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि केंद्र सरकार के मुफ्त अनाज वितरण और पुडुचेरी केंद्र




शासित प्रदेश द्वारा अतिरिक्त अनाज वितरण के कारण परिवारों के भोजन पर होने वाला खर्च 50 प्रतिशत तक कम हो गया है। मुफ्त अनाज वितरण से प्राप्त बचत का उपयोग लोग दूध, सब्जी आदि जैसी अन्य पौष्टिक वस्तुओं की खरीद के लिए कर रहे हैं। इससे न केवल खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि भारत और विश्व के लिए स्वस्थ और तंदुरुस्त युवा आबादी और कुशल श्रमिकों का सृजन भी होता है। उन्होंने आगे बताया कि इस पायलट परियोजना का जल्द ही 3-4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार किया जाएगा और परिणामों के गहन विश्लेषण के बाद सीबीडीसी पहल को आगे बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

श्री जोशी ने यह भी बताया कि लाभार्थियों से उनकी पात्रता के अनुसार अनाज की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए प्रति माह 20 लाख कॉल किए जा रहे हैं। "सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास" की भावना का अनुसरण करते हुए, श्री जोशी ने देश के सभी नागरिकों से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित देश के कल्याण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का आग्रह किया।

इस अवसर पर, पुडुचेरी के उपराज्यपाल श्री के. कैलाशनाथन ने कहा कि आज का दिन पुडुचेरी के वंचित और मेहनती नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह हमारे परिवारों के लिए गर्व का दिन है और हमारे केंद्र शासित प्रदेश की खाद्य सुरक्षा में एक नया अध्याय लिखने का दिन है। भोजन केवल एक वस्तु नहीं है; यह एक मौलिक मानवाधिकार है। उद्देश्य स्पष्ट है: "इस देश का कोई भी नागरिक भूख से पीड़ित न हो।" केंद्र और राज्य सरकारें खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। इन योजनाओं की वास्तविक सफलता अंतिम उपयोगकर्ता तक उनकी निर्बाध पहुंच में निहित है। हमारा लक्ष्य बिचौलियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, यह सुनिश्चित करना है कि लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे और अपात्र लोगों को इससे वंचित रखा जाए। सरकारी सहायता सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए आधार से जुड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली पुडुचेरी में लागू की गई है और यह प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश में सीबीडीसी के कार्यान्वयन और नागरिक सशक्तिकरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वितरण में पारदर्शिता के संदर्भ में सकारात्मक परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है।

इस अवसर पर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री श्री एन रंगासामी ने खाद्यान्न वितरण में बदलाव लाने और पुडुचेरी के नागरिकों को सशक्त बनाने वाली सीबीडीसी की नई पहल की सराहना की। उन्होंने बताया कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत अपने लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। भारत सरकार द्वारा धन हस्तांतरण और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपनी योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति गरीबों की खाद्य सुरक्षा की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा कर रही है और उन्हें भूख से बचा रही है। डीबीटी के माध्यम से बैंक में और अब सीबीडीसी के माध्यम से वॉलेट में आ रही राशि लाभार्थियों के प्रोत्साहन को बढ़ाएगी, उन्हें आत्मविश्वास देगी और उन्हें उपलब्ध धन से अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाएगी। यह वास्तव में एक महान कदम है जो बिना किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति के मध्यस्थ के सीधे सीबीडीसी वॉलेट के माध्यम से लाभार्थियों को धन उपलब्ध करा रहा है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश सीबीडीसी के इस पायलट प्रोजेक्ट और इसके कार्यान्वयन के नेक इरादों का समर्थन कर रहा है। उन्होंने सीबीडीसी से लाभार्थियों को पात्र धन हस्तांतरण की पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता पर प्रसन्नता व्यक्त की।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (पीडीएस) में सीबीडीसी के शुभारंभ के अवसर पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कहा कि पीएमजीकेएवाई के तहत सब्सिडी वितरण हेतु पुडुचेरी में सीबीडीसी की शुरूआत लाभार्थियों तक त्वरित, पारदर्शी और कुशल तरीके से सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि यह पहल जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) पर आधारित है और डिजिटल सशक्तिकरण को और मजबूत करती है। फीचर फोन उपयोगकताओं को शामिल करने पर विशेष जोर देते हुए इसकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह प्रणाली लाभार्थियों को एप्लिकेशन के माध्यम से आस-पास के अधिकृत व्यापारी प्रतिष्ठानों का पता लगाने में भी सक्षम बनाती है। उन्होंने बताया कि सीबीडीसी आधारित पीडीएस मॉडल का विस्तार पुडुचेरी में किया जाएगा और बाद में इसे चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में भी लागू किया जाएगा, साथ ही धीरे-धीरे पूरे देश में इसका विस्तार करने की योजना है। उन्होंने सीबीडीसी के पायलट शुभारंभ में आरबीआई, केनरा बैंक और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के प्रयासों और सहयोग की सराहना की।

यह पहल जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्य सब्सिडी के वितरण में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल रुपये को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) ढांचे में एकीकृत किया गया है। इस पायलट परियोजना के तहत, खाद्य सब्सिडी चिन्हित लाभार्थियों के सीबीडीसी वॉलेट में प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) टोकन के रूप में सीधे जमा की जाएगी। इन टोकनों का उपयोग केवल अधिकृत व्यापारियों और उचित मूल्य दुकानों (एफपीएस) पर पात्र खाद्यान्न की खरीद के लिए किया जा सकेगा, जिससे सब्सिडी का उद्देश्य-आधारित उपयोग सुनिश्चित होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

पिछले कई वर्षों में, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने भारत के खाद्य सुरक्षा तंत्र के व्यापक डिजिटल रूपांतरण का कार्य किया है। प्रमुख पहलों में वन नेशन वन राशन कार्ड ढांचे के तहत राशन कार्डों का पूर्णतः डिजिटलीकरण और राष्ट्रव्यापी सुवा'ता, आधार-सक्षम प्रमाणीकरण और वास्तविक समय में लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए ई-पीओएस उपकरणों की तैनाती और राइटफुल टारगेटिंग डैशबोर्ड के माध्यम से डेटा-आधारित सत्यापन का कार्यान्वयन शामिल हैं। अन्न चक्र के माध्यम से डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन और अन्न सहायता जैसी सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणालियों ने पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को और भी बेहतर बनाया है। सीबीडीसी-आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा पायलट परियोजना, पीडीएस संरचना में एक प्रोग्रामेबल संप्रभु डिजिटल भुगतान परत को एकीकृत करके इस सुधार यात्रा का अगला चरण है।

सीमित संख्या में लाभार्थियों के साथ शुरू हुई यह पायलट परियोजना, कल्याणकारी वितरण में प्रौद्योगिकी के एकीकरण, पारदर्शिता को सुदृढ़ करने और अंतिम छोर तक सेवा वितरण के लिए अधिक कुशल और जवाबदेह शासन ढांचा तैयार करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम साबित होने की उम्मीद है।

केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने सीबीडीसी आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुडुचेरी के उपराज्यपाल श्री के. कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री एन. रंगासामी, विधानसभा अध्यक्ष श्री आर. सेल्वम, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य मंत्री श्री पी.आर.एन. थिरुमुरुगन, पुडुचेरी सरकार के लोक निर्माण मंत्री श्री के. लक्ष्मीनारायण तथा केंद्र सरकार, पुडुचेरी सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और केनरा बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

# होम क्रेडिट इंडिया ने पेश किया होली म्यूजिकल कहो इएमआई को हाँ के साथ सुरक्षित वित्तीय विकल्पों का उत्सव

होम क्रेडिट इंडिया ने पेश किया होली म्यूजिकल KahoEMIKoHaan के साथ सुरक्षित वित्तीय विकल्पों का उत्सव

26 फरवरी 2026: अग्रणी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, होम क्रेडिट इंडिया ने आज अपने नए ब्रांड कैंपेन KahoEMIKoHaan की शुरूआत का एलान किया। होली के जीवंत उत्साह और ब्रांड के मूल दर्शन्ेल्लॅंि३ पर आधारित यह अभियान, क्रेडिट के प्रति भारतीयों के भावनात्मक जुड़ाव को संकोच और संदेह से बदलकर आत्मविश्वास और स्मार्ट वित्तीय विकल्पों में बदलना चाहता है।

KahoEMIKoHaan के केंद्र में एक सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि निहित है - जहाँ भारतीय बिना किसी संकोच के रंगों के साथ होली का आनंद लेते हैं, वहीं ईएमआई या लोन जैसे वित्तीय निर्णय लेते समय वे अक्सर रुकते हैं और खुद पर संदेह करते हैं। इस म्यूज़िकल कैंपेन के माध्यम से, होम क्रेडिट इंडिया उपभोक्ताओं को क्रेडिट को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले एक 'सार्थक माध्यम' के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उन्हें बिना किसी आत्म-ग्लानि या संदेह के प्रगति के लिए 'हाँ' कहने के लिए सशक्त बनाता है।

यह अभियान अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और लिंक्डइन सहित होम क्रेडिट इंडिया के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव है।

कैंपेन की कथावस्तु

यह कहानी होली के आगमन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें ऐसे दिल को छू लेने वाले बोल हैं जो रुक-रुक कर चलती जिंदगी की लय को दशार्ते हैं—जहाँ सपने अधूरे लगते हैं, जेब थोड़ी खाली महसूस होती है और रोजमर्रा की वित्तीय दिक्कतों के बीच मन के रंग भी फीके पड़ने लगते हैं। इस जीवंत चित्रण के बीच संकोच के वो आम पल दिखाए गए हैं जिनसे हर कोई जुड़ाव महसूस करता है—एक व्यक्ति जो अपने पुराने स्कूटर के साथ संघर्ष कर रहा है, एक युवती जो त्यौहार की रील रिकॉर्ड करते समय फोन खराब होने पर निराश हो जाती है, कॉलेज एडमिशन फॉर्म के पेमेंट पेज पर रुके हुए भाई-बहन, और एक नवविवाहित जोड़ा जो ऑनलाइन पसंद आए डाइनिंग टेबल की कीमत देखकर चुपचाप पीछे हट जाता है।

जैसे-जैसे उनके चारों ओर उत्सव जारी रहता है, उनके मन का संकोच और स्पष्ट होने लगता है। सपने तो जीवित हैं—पर अनिश्चितता उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। उत्सव और इस संयम के बीच एक गहरा अहसास उभरता है: कि जिंदगी रुकती नहीं और आकांक्षाएं कभी धुंधली नहीं पड़तीं—बस झिझक ही रास्ते की बाधा है।

भावनात्मक बदलाव की शुरूआत बहुत छोटी सी होती है। स्क्रीन पर होम क्रेडिट का एक नोटिफिकेशन चमकता है। किसी की नजर टू-व्हीलर शोरूम के बाहर लगे बैनर पर पड़ती है। होम




क्रेडिट ऐप पर कुछ ही टैप्स संदेह को भरोसे में बदल देते हैं। छोटे-छोटे निर्णय अब आत्मविश्वास से भरे विकल्पों का रूप ले लेते हैं।

इसके बाद शुरू होता है रंगों भरा बदलाव—नए फोन से ली गई होली की सेल्फी, नए स्कूटर पर एक खुशनुमा सवारी, एडमिशन मिलने की खुशी मनाते भाई-बहन, और पड़ोसियों के साथ गुजिया बांटते हुए अपना नया डाइनिंग टेबल सजाता एक जोड़ा। इन सभी यात्राओं में, होम क्रेडिट एक शांत लेकिन भरोसेमंद साथी की भूमिका निभाता है, जो इस बात को पुख्ता करता है कि ईएमआई चुनना अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक समझदारी भरा और जिम्मेदार कदम हो सकता है।

फिल्म का समापन होली के एक सामूहिक उत्सव के साथ होता है, जहाँ सभी पात्र रंगों, खुशी और आत्मविश्वास के एक जीवंत दृश्य में एक साथ आते हैं—जो एक सरल संदेश को रेखांकित करता है: ईएमआई को 'हाँ' कहना, जीवन की प्रगति को 'हाँ' कहना हो सकता है।

कैंपेन पर बात करते हुए, होम क्रेडिट इंडिया के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, आशीष तिवारी ने कहा: "होली स्वतंत्रता, रंगों और एकजुटता का प्रतीक है और इसका जश्न मनाती है; हम यही भावना लोगों के वित्तीय निर्णयों के प्रति नजरिए में भी लाना चाहते थे। डॅंङ्गएटक्ङङ्गलंल्ल के साथ, हम ईएमआई और लोन से जुड़ी भावनात्मक हिचकिचाहट को आत्मविश्वास में बदल रहे हैं, और क्रेडिट को एक भरोसेमंद व जिम्मेदार विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं जो लोगों को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारा लक्ष्य ग्राहकों को उनकी आकांक्षाओं के लिए 'हाँ' कहने हेतु सशक्त बनाना है—चाहे वह स्मार्टफोन या घरेलू उपकरणों को अपग्रेड करना हो, टू-व्हीलर खरीदना हो, या बड़ी योजनाओं को आकार देना हो। होम क्रेडिट इंडिया में, हम सरल, पारदर्शी, तकनीक-आधारित और सुलभ वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो ग्राहकों

# सर्वोच्च 3 भारतीय ओ.एम.सी ने पाईन लैब्स को पूरे देश में डिजिटल पेमेंट के आधुनिकीकरण के लिए बहुवर्षीय कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किया

लखनऊ, 26 फरवरी 2025: ग्लोबल फिनटेक प्लेटफॉर्म, पाईन लैब्स को भारत में तीन प्रमुख ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनियों (ओ.एम.सी) द्वारा कई महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किए गए हैं। ये तीन कंपनियाँ, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल) हैं।

इन तीन ओ.एम.सी से मिले कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, पाईन लैब्स द्वारा भारत में पेट्रोल पंपों और मर्चेंट आउटलेट्स पर डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर का क्रियान्वयन, प्रबंधन और रखरखाव किया जाएगा। इन बहुवर्षीय कॉन्ट्रैक्ट्स का उद्देश्य पॉइंट ऑफ सेल पर पैसे के तीव्र, सुरक्षित और सुगम लेनदेन के लिए पेमेंट रेल को संभालने में पाईन लैब्स की विशेषज्ञता का उपयोग करना है। इसके अंतर्गत भारत में कुल 130,000 डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाईस तुरंत स्थापित की जाएंगी और संभाली जाएंगी।

आई.ओ.सी.एल के लिए पाईन लैब्स द्वारा उनका लॉयल्टी रिवाड्र्स प्लेटफॉर्म, एक्सट्रापॉवर संभाला जाएगा, जिसका उपयोग भारत में लाखों फ्लीट ऑपरेटर करते हैं। यह प्रोग्राम मजबूत ए.पी.आई इंटीग्रेशन द्वारा निर्मित है, जो फ्यूल मैनेजमेंट, फ्लीट एनालिटिक्स, ट्रिप मैनेजमेंट, सिक्योर चिप और पिन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन, जैसे कार्ड, मोबाईल और आरएफआईडी पेमेंट सेवाएं संभव बनाता है।

बी. अमरीश राउ, सी.ई.ओ, पाईन लैब्स लिमिटेड ने कहा, "हम अपने टेक कौशल और भारत में सर्वोच्च ओ.एम.सी के विस्तृत रिटेल फुटप्रिंट्स की मदद से एक टेक-फर्स्ट और मजबूत पेमेंट्स इन्फ्रा एवं विश्वस्तर के प्रीपेड लॉयल्टी रिवार्ड सिस्टम का विकास कर रहे हैं। पाईन लैब्स के सॉफ्टवेयर-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ हम भारत में फ्यूल रिटेल कॉमर्स के तीव्र डिजिटाईजेशन के लिए प्रोडक्ट फीचर ज्यादा तेजी से पेश करेंगे, जिससे ऑन-साईट हस्तक्षेप कम से कम होगा और एक यूनिफाईड रिवार्ड/लॉयल्टी प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा।"

पब्लिक सेक्टर के दिग्गजों के साथ यह फिनटेक पार्टनरशिप आसान, सुरक्षित और सुगम डिजिटल पेमेंट्स एवं लॉयल्टी रिवार्ड अनुभवों के माध्यम से प्रमुख भारतीय ओ.एम.सी और पाईन लैब्स द्वारा ग्राहकों पर केंद्रित प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है।

# फेमिना मिस इंडिया उत्तर प्रदेश ग्रैंड फिनाले 2026 का भव्य आयोजन

लखनऊ, फेमिना मिस इंडिया उत्तर प्रदेश ग्रैंड फिनाले 2026 का भव्य आयोजन BBD University, लखनऊ में 25 फरवरी को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सौंदर्य प्रतियोगिता में लखनऊ की सानिया मुखर्जी को फेमिना मिस इंडिया उत्तर प्रदेश 2026 का ताज पहनाया गया।

सानिया मुखर्जी का चयन प्रदेश भर से आई 500 से अधिक प्रतिभागियों में से तीन चरणों की ऑडिशन प्रक्रिया के बाद चुनी गई 16 स्टेट फाइनलिस्ट्स में से किया गया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और मंच प्रस्तुति के माध्यम से अपनी प्रतिभा




का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

इस भव्य आयोजन की शोभा Nikita Porwal, वर्तमान फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, की गरिमामयी उपस्थिति से और भी बढ़ गई, जिन्होंने कार्यक्रम को विशेष और प्रेरणादायक बना दिया।

इस अवसर पर श्री अमित सैमसन नानू, संस्थापक, कैटवॉक अकादमी, स्टेट लाइसेंसी, फेमिना मिस इंडिया उत्तर प्रदेश, ने बीबीडी ग्रुप के नेतृत्व—श्रीमती अलका दास गुप्ता (माननीय चेयरपर्सन), श्री विराज सागर (माननीय प्रेसिडेंट एवं प्रो-चांसलर, बीबीडी यूनिवर्सिटी), सुश्री सोनांक्षी दास गुप्ता एवं सुश्री देवांशी दास गुप्ता (माननीय वाइस प्रेसिडेंट्स)—के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आयोजन को सशक्त बनाने में उनके सहयोग की सराहना की।

कार्यक्रम को Geetanjali Salon (मेकअप पार्टनर), Gharha Bhandar , Ganpati Collection एवं The vogue Nari (वार्डरोब पार्टनर), Danbro by Mr. Brown (फूड एंड बेवरेज पार्टनर), डिजाइनर Ashfaq Ahmad (ईवनिंग गाउन्स), JD Institute (बैकस्टेज सपोर्ट), A&M Dental Station (स्माइल पार्टनर), ummietummie (गिफ्टिंग पार्टनर) तथा Marshal Security (सिक्योरिटी पार्टनर) का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

# अमृता की आजाद रूह को कथक के घुंघरू देंगे आवाज, लखनऊ में सजेगी साहित्य और कला की महफिल

लखनऊ। मैं तुम्हें फिर मिलूँगी, कहने वाली कलम की मलिका अमृता प्रीतम एक बार फिर लखनऊ की सरजमीं पर जिंदा होंगी। आगामी 28 फरवरी को संत गाडगे प्रेक्षागृह में कल्चरल क्वेस्ट की ओर से नृत्य नाटिका आजाद रूह का मंचन किया जा रहा है।

यह मात्र एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सफर है, विभाजन के उस गहरे दर्द से लेकर अमृता और इमरोज की उस खामोश मोहब्बत तक, जिसने दुनिया को प्यार के नए मायने सिखाए। कथक गुरु सुरभि सिंह के निर्देशन और संगीत में पिरोई गई यह नाटिका नारी के संघर्ष, साम्प्रदायिकता की आग और एक आजाद रूह की



बेबाकी को मंच पर जीवंत करेगी।

शाम का आकर्षण सिर्फ नृत्य तक सीमित नहीं है। इस मौके पर संजय मल्होत्रा हमनवा की बहुप्रतीक्षित पुस्तक अमृत इमरोज का विमोचन भी होगा। साथ ही, साहित्य की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाली 11 हस्तियों को अमृता प्रीतम सम्मान से नवाजा जाएगा। सम्मानित होने वालों में पद्मश्री विद्या विन्दु सिंह और हिमांशु वाजपेई जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं।

यह कार्यक्रम उन तमाम रूहों को समर्पित है जो सरहदों और रूढ़ियों से परे होकर जीना जानती हैं।

कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना विकास मंत्री, दया शंकर सिंह, परिवहन मंत्री और लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल उपस्थित रहेंगी। तारीख याद रखिएगा 28 फरवरी, शाम 6:30 बजे। आइए, उस रूह को महसूस करें जिसने कभी झुकना नहीं सीखा।

# 'किसी को तो जवाबदेह ठहराना होगा', एनसीआरटी की पाठ्यपुस्तक विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की एक पाठ्यपुस्तक पर कड़ी नाराजगी जताई है। इस किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' नाम का एक अध्याय शामिल था, जिस पर काफी विवाद हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्याय के प्रकाशन पर पूरी तरह रोक लगा दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस बात का पता लगाने का निर्देश दिया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए किसी न किसी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

यह कैबिनेट बैठक नए बने सेवा तीर्थ में आयोजित पहली बैठक थी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि कक्षा 8 के बच्चों को ऐसी बातें क्यों पढ़ाई जा रही हैं और पाठ्यपुस्तकों की सामग्री की निगरानी कौन करता है। सूत्रों के अनुसार, शिक्षा मंत्री के समझाने की कोशिश के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर अड़े रहे कि इस गलती के लिए किसी को जिम्मेदारी लेनी ही होगी। सरकार में मौजूद सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री इस घटना से नाखुश और नाराज थे।

गुरुवार को झारखंड में पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वे इस घटना से 'बेहद दुखी' हैं। उन्होंने कहा कि जब यह मामला उनके संज्ञान में आया, तो उन्होंने एनसीईआरटी को पुस्तक वापस लेने का निर्देश दिया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका के प्रति हमारा पूर्ण सम्मान है। न्यायपालिका ने जो कहा है, हम उसे स्वीकार करेंगे और उसका पालन करेंगे। जो कुछ हुआ है उससे मैं अत्यंत दुखी हूं और इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। जब यह मामला मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने तुरंत एनसीईआरटी को पुस्तकों को वापस लेने का निर्देश दिया, ताकि वे आगे प्रसारित न हों।

मंत्री ने आगे कहा कि न्यायपालिका का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था‌‌ सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और इसकी जांच की जाएगी। इस अध्याय को तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम न्यायपालिका को आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी।

25 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी थी कि एनसीईआरटी द्वारा जारी कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' नामक अध्याय के अंतर्गत 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' शीर्षक से एक खंड शामिल किया गया है। इस अध्याय में भारतीय न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली 'चुनौतियों' में 'न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार' और 'लंबित मामले‌‌' का उल्लेख किया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीईआरटी मुद्दे पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय न्यायपालिका जितनी स्वतंत्र और न्यायसंगत कोई अन्य संस्था नहीं है। हम सभी भारतीय न्यायपालिका के प्रति सम्मान का भाव, मान का भाव और स्वाभिमान का भाव रखते हैं।

उखक सूर्यकांत कराएंगे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की गहन जाँच

सीजेआई ने कहा, 'मैं रजिस्ट्री के कामकाज की गहन जांच का आदेश दूंगा। रजिस्ट्री में ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 20-30 वर्षों से यहां हैं। वे सोचते हैं कि हम (न्यायाधीश) सभी अस्थायी हैं और वे स्थायी हैं। इसलिए, चीजें उनकी मर्जी के मुताबिक ही होनी चाहिए। यदि मैं अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे ठीक नहीं करता, तो मैं अपने कर्तव्य में विफल हो जाऊंगा।'

# सीएम योगी का जापान-सिंगापुर प्लान सफल, 5 लाख नए रोजगार और 'जापान सिटी' से बदलेगी यूपी की सूरत

यामानाशी/लखनऊ। (जीएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चार दिवसीय सिंगापुर व जापान दौरा अभूतपूर्व रूप से सफल रहा। इस यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार को 1.5 लाख करोड़ के एमओयू तथा 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इन निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से 5 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और यह उत्तर प्रदेश को वर्ष 2029-30 तक वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगा।

यूपी की कानून-व्यवस्था और पारदर्शिता पर वैश्विक विश्वास

मीडियाकर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि जापान में 90,000 करोड़ के एमओयू और लगभग 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमओयू और लगभग 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का कार्य इन्वेस्ट यूपी और राज्य के अन्य संबंधित विभाग समयबद्ध ढंग से करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरी यात्रा के दौरान यह स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि कानून-व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रारंभ से रहा फोकस अब परिणाम दे रहा है।

यह वीडियो भी देखें

टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग और प्रशासनिक पारदर्शिता से वैश्विक निवेशकों का विश्वास अर्जित होता है और यही विश्वास दोनों देशों में उत्तर प्रदेश के प्रति दिखाई दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया गया है तथा रूल ऑफ लॉ के अनुरूप बेहतर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसका सकारात्मक प्रभाव निवेश के माहौल पर पड़ा है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यामानाशी के गवर्नर अगस्त माह में लगभग 200 जापानी सीईओ के प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तर प्रदेश आने वाले हैं, जो संभावित निवेश को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इसी प्रकार सिंगापुर से भी एक बड़ा बिजनेस डेलिगेशन उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आने को उत्सुक है। सीएम योगी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय के साथ संवाद का अवसर भी मिला। सिंगापुर, टोक्यो और यामानाशी, तीनों स्थानों पर भारतीय समुदाय के साथ बड़े और उत्साहपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुए, जिन्होंने भारत और उत्तर प्रदेश के प्रति सकारात्मकता और विश्वास को और सुदृढ़ किया।

5 लाख रोजगार की संभावना

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास पर्याप्त स्केल, बड़ा लैंड बैंक और निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट सेक्टोरल पॉलिसियां हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था निवेशकों के विश्वास को मजबूत कर रही है। यदि 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू और 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरते हैं, तो 5 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सिंगापुर और जापान की यह यात्रा केवल समझौतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किलिंग, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास की नई दिशा तय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दौरा उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध होगा।

नए अवसरों की शुरूआत

सिंगापुर व जापान के चार दिवसीय दौरे के समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यात्रा का चौथा दिन है और एक प्रकार से यह यात्रा के

# उपराष्ट्रपति 27 फरवरी को आईआईएमसी के 57वें दीक्षांत समारोह में

**आईआईएमसी के 57वें दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन होगा, शीर्ष निष्पादन करने वालों को 35 पदक प्रदान किए जाएंगे**

(जीएनएस)।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं आईआईएमसी के कुलाधिपति श्री अश्विनी वैष्णव और आईआईएमसी में बनने वाले नए शैक्षणिक और छात्रावास ब्लॉकों की आधारशिला रखने के समारोह की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) 2024-25 बैच के लिए 57वां दीक्षांत समारोह 27 फरवरी, 2026 को अपने नई दिल्ली परिसर में आयोजित करेगा।

उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि आईआईएमसी के कुलाधिपति और सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

दीक्षांत समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू, आईआईएमसी सोसायटी के अध्यक्ष श्री आर. जगन्नाथन, आईआईएमसी की कुलपति डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौर और आईआईएमसी के रजिस्ट्रार श्री एल. मधु नाग भी उपस्थित रहेंगे। संस्थान के संकाय सदस्य और कर्मचारी भी इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में उपस्थित होकर स्नातक छात्रों का मनोबल बढ़ाएंगे।

विभिन्न परिसरों में पत्रकारिता (अंग्रेजी, हिंदी, रेडियो एवं टीवी, डिजिटल मीडिया, ओडिया, उर्दू, मराठी और मलयालम), विज्ञापन और जनसंपर्क सहित स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के छात्र जिन्होंने 2024-25 में अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, उन्हें डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह में डिप्लोमा के अतिरिक्त सभी छह परिसरों के प्रत्येक पाठ्यक्रम के शीर्ष छात्रों को 35 पदक प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से 23 में नकद पुरस्कार शामिल हैं।

उपराष्ट्रपति, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सहित अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में, नई दिल्ली स्थित आईआईएमसी में नए शैक्षणिक ब्लॉक और छात्रावास ब्लॉक की आधारशिला रखी जाएगी। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा मंत्रालय और संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इनक्यूबेशन सेंटर में स्थित क्रिएटर्स लाउंज का भी उद्घाटन किया जाएगा।

# भारतीय रेल में नवाचार को बढ़ावा देने और दावा न्यायाधिकरण की प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए तीसरे और चौथे सुधार के रूप में रेल टेक पोर्टल के लॉन्च की घोषणा

(जीएनएस)।

रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने प्रौद्योगिकी-संचालित शासन और नवाचार-आधारित परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज भारतीय रेल की प्रमुख "52 सप्ताह में 52 सुधार" पहल के तहत सुधार संख्या तीन और सुधार संख्या चार के रूप में रेल टेक नीति और रेल दावा न्यायाधिकरण (आरसीटी) के पूर्ण डिजिटलीकरण की घोषणा की।

रेल प्रौद्योगिकी नीति सुधार

रेल प्रौद्योगिकी नीति का उद्देश्य भारतीय रेल में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स, उद्योग और संस्थानों को शामिल करना है। नई नीति नवप्रवर्तकों के चयन को सरल बनाती है और नवोन्मेषण के लिए एक समर्पित "रेल प्रौद्योगिकी पोर्टल" की शुरूआत करती है। कोई भी नवप्रवर्तक या विभागीय उपयोगकर्ता प्रस्तावों को एकल-चरण में विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने के माध्यम से नवाचार चुनौतियों की शुरूआत कर सकता है।

इस नीति में उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान किया गया है, विस्तार अनुदान को तीन गुना से अधिक बढ़ाया गया है और प्रोटोटाइप विकास तथा परीक्षणों के लिए अधिकतम अनुदान को दोगुना कर दिया गया है।

प्रमुख नवोन्मेषण क्षेत्रों में एआई-आधारित एलीफेंट इंट्रुजन डिटेक्शन सिस्टम (ईआईडीएस), कोचों में एआई-आधारित फायर डिटेक्शन सिस्टम, ड्रोन-आधारित ब्रोकेन रेल डिटेक्शन सिस्टम, रेल स्ट्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्सल वैन (वीपीयू) पर सेंसर-आधारित लोड कैलकुलेशन डिवाइस, कोचों पर सौर पैनल, एआई-आधारित कोच सफाई निगरानी प्रणाली, कोहरे वाले मौसम में बाधा पहचान और एआई-आधारित पेंशन और विवाद समाधान प्रणाली शामिल हैं।






श्री वैष्णव ने तीसरे सुधार की रूपरेखा बताते हुए कहा कि रेल प्रौद्योगिकी नीति का उद्देश्य रेलवे में प्रौद्योगिकी का व्यापक और व्यवस्थित समावेश करना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों को निश्चित रूप से भारतीय रेल से एक संरचित, सार्थक और सरल तरीके से जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को, जिसके पास कोई सशक्त प्रौद्योगिकीय विचार हों, एक समर्पित रेल टेक पोर्टल के माध्यम से रेल से संपर्क करने की सुविधा मिलनी चाहिए, जो पूरी तरह से डिजिटल और संपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से कार्य करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य कठोर विनिदेर्शों पर आधारित वेंडर चयन की पूर्व जटिल प्रणाली से हटकर, नई प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और अंगीकरण पर केंद्रित एक सरल, नवोन्मेषण-संचालित संरचना तैयार करना है।

श्री वैष्णव ने कहा कि रेल प्रौद्योगिकी नीति को रक्षा क्षेत्र में आईडेक्स पहल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्टार्टअप ढांचे और दूरसंचार क्षेत्र की नवाचार नीतियों जैसे सफल मॉडलों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है। इन अनुभवों से सीखते हुए, भारतीय रेल ने प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने और एक पारदर्शी, सरल और नवोन्मेषण-अनुकूल इको-सिस्टम बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि यदि यह सफल होता है, तो यह मॉडल दूसरे सेक्टरों के लिए भी एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है।

वित्तपोषण संरचना की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि जब कोई स्टार्टअप या नवप्रवर्तक कोई व्यवहार्य प्रौद्योगिकीय समाधान प्रस्तावित करता है, उदाहरण के लिए रेलवे ट्रैक के पास हाथियों का पता लगाने के लिए एआई-आधारित कैमरा सिस्टम, तो रेलवे आवश्यक विकास निधि का 50 प्रतिशत तक प्रदान करेगा। परियोजना के सफल साबित होने पर समाधान के विस्तार को सक्षम बनाने के लिए व्यापक स्तर पर दीर्घकालिक ऑर्डर दिए जाएंगे। यह नीति केवल प्रयोग करने के लिए नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि सफल नवोन्मेषणों को व्यापक स्तर पर लागू किया जाए।

उन्होंने नवाचार के लिए कई संभावित अनुप्रयोग क्षेत्रों का उल्लेख किया, जिनमें यात्री सुरक्षा के लिए एआई-सक्षम सीसीटीवी सिस्टम शामिल हैं। उन्होंने केरल में हाल ही में हुई एक घटना में सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों को तुरंत पकड़ने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सक्रिय अपराध पहचान प्रणाली, पूवार्नुमानित निगरानी और उन्नत यात्री सुरक्षा प्रौद्योगिकियां रेलवे सुरक्षा को अत्यधिक मजबूत कर सकती हैं। उन्होंने दुर्घटनाओं से पहले पटरियों में त्रुटियों या दोषों का पता लगाने के लिए रडार, एआई, इन्फ्रारेड कैमरों और अल्ट्रासोनिक तकनीकों का उपयोग करके उन्नत ट्रैक निगरानी समाधानों की आवश्यकता पर भी बल दिया। ओवरहेड तारों में विद्युत मापदंडों का विश्लेषण करने में सक्षम पूवार्नुमानित प्रौद्योगिकीय का भी उल्लेख किया गया, जो संभावित विफलताओं का पूवार्नुमान लगा सकती हैं। ये ऐसे आशाजनक क्षेत्र हैं जिन पर स्टार्टअप्स पहले से ही काम कर रहे हैं।

# केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज बिहार के अररिया में सशस्त्र सीमा बल के जवानों से संवाद किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज बिहार के अररिया में सशस्त्र सीमा बल के जवानों से संवाद किया और बॉर्डर आउट पोस्ट लेटी व इंदरवा का उद्घाटन और ररइ की विविध परियोजनाओं का ई-लोकार्पण और ई-शिलान्यास किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय, बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, केन्द्रीय गृह सचिव, निदेशक, आसूचना ब्यूरो, सचिव, सीमा प्रबंधन, गृह मंत्रालय और महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।



अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवानों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगभग ₹170 करोड़ की लागत से अनेक प्रकार के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 2014 से देश के सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के जवानों की सुविधाओं के लिए एक संवेदनापूर्ण कार्ययोजना बनाई है और इसी के तहत आज यह शिलान्यास और लोकार्पण हुए हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज यहां पर ररइ से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा सड़क योजना के तहत 554 किलोमीटर सीमा सड़क को भी स्वीकृत किया गया है, जिसके 18 खंडों में से 14 खंडों पर कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वीकृत 2468 करोड़ रूपए में से 2336 करोड़ रूपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह सड़क बनने के बाद ररइ के जवानों की निगरानी की क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमने चुनाव में बिहार की जनता से वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मतदाता सूची से घुसपैठियों का नाम नहीं हटाएंगे बल्कि एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर भारत से बाहर भेजेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश को घुसपठियों से मुक्त करना सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं है बल्कि मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कर इसकी शुरूआत करेंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि घुसपैठिए सिर्फ हमारे चुनावों को प्रभावित नहीं करते बल्कि गरीबों के राशन में से भी हिस्सा ले जाते हैं, हमारे युवाओं की रोजगार की संभावनाओं को भी क्षीण करते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पूरे देश को हर स्तर पर काम कर घुसपैठियों से मुक्त कराने का अभियान चलाना होगा। श्री शाह ने कहा कि देश की सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उन्हें सबसे पहले इस अभियान के तहत हटा दिया जाएगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश में स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं करता है। श्री शाह ने कहा कि अतिक्रमण से, घुसपैठ से होने वाला डेमोग्राफी बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल, तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है और मोदी सरकार इसका स्थायी समाधन करेगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जनसांख्यिकी परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड हैं। उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी तब हमारा सबसे पहला एजेंडा होगा सीमा पर बाड़ का काम समाप्त करना और एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर देश से बाहर भेजना।

श्री अमित शाह ने कहा कि ररइ को एक जमाने में विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था और हमारे सीमांत गांवों की सांस्कृतिक पहचान, इतिहास और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की ज़िम्मेदारी ररइ पर ही थी। उन्होंने कहा कि अटल जी की सरकार के समय ररइ के ज़िम्मे नेपाल-भूटान सीमा की सुरक्षा का काम आया। उन्होंने कहा कि 2001 में 1751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल की बाड़रहित सीमा की सुरक्षा ररइ के हिस्से में आई। 2004 से 699 किलोमीटर लंबी भूटान की सीमाओं की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी ररइ को सौंपी गई। श्री शाह ने कहा कि ररइ के जवानों ने हर जगह पर कठिनतम परिस्थितियों में सीमाओं की रखवाली और सीमांत गांवों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की कुशलता की हमेशा चिंता की।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि हमारे देश के दुश्मन और देश को नुकसान की मंशा रखने वाले वाले तत्व देश के रास्ते का उपयोग कर भारत में प्रवेश न करें। उन्होंने कहा कि इसीलिए ररइ को हमेशा अपनी नजर पैनी रखनी होगी और अपनी सूचना के स्रोत को भी मजबूत रखना होगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि सीमा की सुरक्षा के साथ-साथ स्मग्लिंग, नारकोटिक्स और अन्य अवैध गतिविधियों पर भी ररइ को पैनी नजर रखनी है। उन्होंने कहा कि ररइ के सभी अधिकारियों को इसके लिए एक रङ्ख्रढ बनानी चाहिए जो सभी संभावित खतरों का आंकलन करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि खुली सीमा की सुरक्षा करते हुए अनेक प्रकार के सीमा सुरक्षा के नए आयामों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वायब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम -2 और वायब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-1 के माध्यम से गांवों की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण सुधार करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे जवानों और उनके परिजनों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलें।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जी न सिर्फ आजादी के संग्राम के अप्रतिम योद्धा थे बल्कि एक निडर देशभक्त भी थे उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जी की कलम में भी बहुत ताकत थी और उन्होंने अपने गद्य और ˉ ˉ ˉ से पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार जगाया। पहले लोग 1857 की सशस्त्र क्रांति को विप्लव के नाम से जानते थे लेकिन वीर सावरकर जी ने उसे स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण से ही पूरे में देश का गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फेंक देने का जज्बा उभर कर आया था।

# भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के करियर के अवसरों को और बेहतर बनाने के लिए 'सहयोग का ढांचा' शुरू किया

(जीएनएस)।

संस्थागत सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने "सहयोग ढांचा" शुरू किया है। इसका मकसद अग्निवीरों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है, जो बतौर आम नागरिक वे बेहतर जीवन बिता सकें।

सेना और रेल मंत्रालय के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य सैन्य से नागरिक करियर में सरल बदलाव सुनिश्चित करना है। इससे रेलवे में रोजगार की संभावनाओं के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी और सेवानिवृत्त कर्मियों की सहायता के लिए एक समर्पित सहायता प्रणाली भी तैयार होगी।

यह सहयोगात्मक ढांचा पूर्व सैनिकों को सार्थक दूसरा करियर मार्ग प्रदान करने और व्यापक राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों का समर्थन करने की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के प्रमुख अवसर

सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों का कल्याण और पुनर्वास, भारतीय रेलवे की नीतिगत संरचना का एक जरुरी घटक है।

पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतुः

स्तर-2/उससे ऊपर के पदों में 10% और स्तर-1 के पदों में 20% क्षैतिज आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, स्तर-2/उससे ऊपर के पदों में 5% और स्तर-1 के पदों में 10% आरक्षण पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया गया है।

वर्ष 2024 और 2025 में, रेलवे की रिक्तियों की अधिसूचनाओं में पूर्व सैनिकों के लिए कुल 14,788 पद आरक्षित किए गए थे, जिनमें शामिल हैं:

स्तर-1 में 6,485 पद

स्तर-2/ऊपर के पदों में 8,303 पद

स्तर-1 (पूर्ववर्ती ग्रुप डी) और स्तर-2/ऊपर के पदों पर भर्ती क्रमशः रेलवे भर्ती केंद्रों (आरआरसी) और रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाती है।

संविदात्मक नियुक्तियों के जरिए तत्काल भर्ती

पूर्व सैनिकों की त्वरित भर्ती को बढ़ावा देने और रिक्त पदों को भरने के लिए, रेल मंत्रालय ने नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक भारतीय रेलवे में संविदा आधार पर पूर्व सैनिकों को 'पॉइंट्समैन' के रूप में भर्ती करने का फैसला किया है।

वर्तमान में जोनल और मंडल स्तर पर 5,000 से अधिक लेवल-1 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अब तक, 9 मंडलों ने पॉइंट्समैन की भर्ती के लिए संबंधित सेना संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सहयोगात्मक ढांचा, सेना भर्ती संगठनों से रेलवे मंडलों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर इन पदों को शीघ्रता से भरने का आ'ान करता है।

राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक शक्तियों का उपयोग

भारतीय रेलवे और भारतीय सेना सेवाकाल के दौरान विकसित बहुमूल्य कौशल, अनुशासन, तकनीकी दक्षता और नेतृत्व गुणों को साझा करते हैं, जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बड़ी संख्या में सैनिक अपेक्षाकृत कम उम्र में ही समृद्ध परिचालन और प्रबंधकीय अनुभव, दृढ़ अनुशासन और राष्ट्रवाद की भावना के साथ सेवानिवृत्त होते हैं।

भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बीच सहयोग रसद और कर्मियों की आवाजाही में अहम भूमिका निभाता है। समर्पित माल गलियारों और उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक जैसी रणनीतिक परियोजनाओं ने सैनिकों और उपकरणों की त्वरित तैनाती क्षमताओं को बढ़ाया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के जरिए कौशल साझाकरण पहलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

यह ढांचा मौजूदा भर्ती प्रणाली के भीतर ही पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों की सुनियोजित भागीदारी को बढ़ावा देता है और दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत करता है। यह पहल राष्ट्रीय अवसंरचना और सुरक्षा समन्वय को मजबूत करते हुए सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के अनुभव और अनुशासन का लाभ उठाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।